>

Title: Need to provide financial assistance to Bihar to facilitate the completion of the long-pending development projects in the State.

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है । शायद भारत सरकार इस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की तैयारी कर रही है । यह सुनने में निश्चित रूप से अच्छा लगेगा । किन्तु यह राज्य कृषि आधारित राज्य है, यह देश का सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश है । विशेष राज्य के दर्जा से उद्योग धंधों को राहत मिलेगी जबकि बिहार राज्य में उद्योग धंधों के लिए जमीन मिलना मुश्किल है। एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल में इस कृषि प्रधान राज्य में उद्योग धंधों के लिए जमीन अधिगृहण नहीं हो पाई क्योंकि किसी भी इलाके में 100-200 एकड़ जमीन मिलना मुश्किल है ।

मेरा अनुरोध है कि यदि बिहार की वर्षों से लंबित परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार पर्याप्त राशि दे तब शायद बिहार का भला होगा । बरौनी को पैट्रोकैमिकल हब बनाना, खाद कारखाना चालू करना, जगदीशपुर, हल्दिया गैस पाइपलाइन का निर्माण, हाजीपुर-सुगौली रेल लाइन निर्माण सहित दर्जनों लंबित परियोजनाओं को पर्याप्त धनराशि देकर बिहार का सही मायने में विकास किया जाये ।